आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 19.12.2025 समय : 0705

<><><><><><><><>

- संसद ने विकसित भारत –गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण): विकसित भारत– जी राम जी बिल 2025 पारित कर दिया है।
- श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
- मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस की ओर से तटीय सुरक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए मछुआरों के साथ बैठक आयोजित की गई।
- डिगलीपुर में ग्राम पंचायतों के राजस्व सृजन पर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

<><><><><><><><>

संसद ने विकसित भारत –गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण): विकसित भारत– जी राम जी बिल 2025 पारित कर दिया है। बिल को राज्यसभा ने कल रात मंजूरी दे दी। लोकसभा ने यह बिल कल पहले ही पास कर दिया था। सरकार इस बिल के माध्यम से वर्ष 2047 में विकसित भारत के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा तैयार करना चाहती है। इस कानून के तहत हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोज़गार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। योजना के लिए केंद्र 60 प्रतिशत और राज्य सरकारें 40 प्रतिशत राशि देंगी। राज्यसभा में चर्चा में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार राष्ट्र प्रथम के आदर्श वाक्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। श्री चौहान ने कहा कि सरकार समाज के वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने लिए अथक प्रयास कर रही है।

<><><><><><><><>

संसद ने भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और विकास –शान्ति विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्य सभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे पहले ही पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के विकास के माध्यम से परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढाना है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले दस वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सतत परमाणु ऊर्जा दोहन और विकास, भारत रूपांतरण विधेयक, 2025 के पारित होने का स्वागत किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसे भारत के प्रौद्योगिकी परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विधेयक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को गति देगा, हरित विनिर्माण को सक्षम बनाएगा और देश तथा दुनिया के लिए स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को निर्णायक गति देगा।

<><><><><><><>

दक्षिण भारत दौरे पर आए भारतीय वन सेवा के 50 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने कल लोक निवास में उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उप–राज्यपाल के साथ एक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें द्वीपों के विकास और पारिस्थितिक संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीप समूह भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कल्याण बोर्ड की 32वीं बैठक कल श्रम आयुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष एवं सचिव एल. कुमार, आईएएस ने की। इस बैठक में केंद्र सरकार के नामांकित प्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान बोर्ड के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष ने द्वीपों के विभिन्न निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही, बोर्ड की गतिविधियों की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल माध्यमों से जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया। इस दौरान बोर्ड ने 13.39 लाख रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दी। यह राशि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत दायर 80 दावों के निपटान के लिए है। बोर्ड इन सभी वित्तीय लाभों और सहायता राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में वितरित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता के. सुगाथन की अध्यक्षता में कल तटीय सुरक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए किशोरीनगर में मछुआरों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्र के एस डी पी ओ अंकेश यादव, मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक तपन कुमार

और कालीघाट थानाध्यक्ष उप–निरीक्षक शिबेंद्र नाथ हलदर उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मछुआरा समुदाय को संवेदनशील बनाना, तटीय सतर्कता बढ़ाना और सामुदायिक पुलिसिंग पहल को और मजबूत करना था। मछुआरों को "आंख और कान" के रूप में संबोधित करते हुए तटीय सुरक्षा में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने मछुआरों से मछली पकड़ने के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि, की सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन को देने का अनुरोध किया। बैठक में प्रधानों, पंचायती राज संस्थान के सदस्यों और 50 से अधिक मछुआरों ने भाग लिया।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान पुलिस ने ऑपरेशन 'कोरल शील्ड' के तहत अभियान चलाकर 8 म्यांमारी घुसपैठियों को पकड़ लिया है। पुलिस ने स्थानीय मछुआरों से मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीमें गठित कर 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने कालीघाट थाना क्षेत्र के निमाई गोप के पास एक इंजन वाली डिंगी को रोककर 02 म्यांमार के घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लगभग 800 किलोग्राम समुद्री खीरा और अन्य सामग्री बरामद की गई। कुछ घुसपैठिए घने जंगलों में भागने में सफल रहे। लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के घने जंगलों और तटीय क्षेत्रों की तलाशी के बाद टीम ने कारेन नाला से 03 तथा नप्पी गोप से 03 और घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। वर्ष 2024 के आंकड़े के अनुसार इस वर्ष मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस ने अब तक कुल 45 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 06 डिंगियां और लगभग 1,500 किलोग्राम समुद्री खीरा शामिल है।

<><><><><><><>

सामुदायिक विकास खंड, डिगलीपुर की ओर से कल 'ग्राम पंचायतों में ओएसआर सृजन के लिए व्यवहार्य वित्तीय मॉडल तैयार करना' विषय पर एक ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाना और उन्हें वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करना था। बैठक में ग्राम पंचायतों के आंतरिक राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों पर चर्चा की गई। खंड विकास अधिकारी एम. राजेंद्र कुमार ने पंचायतों के लिए 'स्वयं के राजस्व स्रोत' फंड के महत्व पर जोर दिया। बीपीएम रंजीता कविराज ने ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत सुभाषग्राम को सर्वाधिक राजस्व सृजन के लिए प्रथम स्थान और ग्राम पंचायत रामकृष्ण ग्राम को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में प्रधानों, पंचायत सचिवों और ग्राम सेवकों ने भाग लिया।

<><><><><><><><>

दक्षिण भारत दौरे पर आए भारतीय वन सेवा के 50 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने कल लोक निवास में उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उप–राज्यपाल के साथ एक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें द्वीपों के विकास और पारिस्थितिक संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

<><><><><><><><>